झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं. 2378/2023

1.एन. सन्स सर्जिकल कंपनी, मालिक- स्वपन घोष, आयु- लगभग 60 वर्ष, पिता- नारेंद्रनाथ घोष, कार्यालय- पटिला चंद्र, डाकघर- पश्चिम मध्यंपुर, थाना- बसीरहाट, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743429

2.स्वपन घोष, आयु- लगभग 60 वर्ष, पिता- नारेंद्रनाथ घोष, निवासी पटिलाचंद्र, पश्चिम मध्यंपुर, डाकघर- पश्चिम मध्यंपुर, पीएस बसीरहाट, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743429

3.सनात कुमार घोष उर्फ सनात घोष, आयु- लगभग 56 वर्ष, पिता- नारेंद्रनाथ घोष, निवासी पटिलाचंद्र, पश्चिम मध्यंपुर, डाकघर- पश्चिम मध्यंपुर, थाना- बसीरहाट, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743429

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2.सुजीत कुमार, औषधि निरीक्षक, हजारीबाग, सदर अस्पताल, डाकघर + थाना + जिला- हजारीबाग

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री सिद्धार्थ रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री पी.डी.अग्रवाल, विशेष लोक अभियोजक

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए दायर की गई है, जिसमें 01.04.2013 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो जी (ड्रग) मामला संख्या 01/2011 के संबंध में माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित किया गया था। इस आदेश के द्वारा, भले ही जमानती गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन रिपोर्ट वापस नहीं की गई थी; बिना किसी कारण के, माननीय मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया और साथ ही 30.05.2018 का आदेश भी, जिसके द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया, और 11.07.2022 का आदेश भी, जो माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, II रामगढ़ द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं की संपत्ति के संबंध में ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स मामला संख्या 01/2011 में संपत्ति की जब्ती के आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें भारतीय ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम की धाराएँ 27(बी) और 27(डी) शामिल हैं, जो माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, रामगढ़ की अदालत में लंबित है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता पर उक्त मामले में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारतीय ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम की धाराएँ 27(बी) और 27(डी) का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ 03.01.2011 को संज्ञान लिया गया था और समन जारी किए गए थे। लेकिन समन की सेवा किए बिना, जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और जमानती गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त किए बिना 01.04.2013 के आदेश द्वारा गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और बिना गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त किए बिना 30.05.2018 के आदेश द्वारा उद्घोषणा जारी की गई और 11.07.2022 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की संपत्ति की जब्ती का आदेश पारित किया गया।

4. याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत जब्ती आदेश को संबंधित प्राधिकरण द्वारा लागू नहीं किया गया है और अभी तक याचिकाकर्ताओं की कोई संपत्ति जब्त नहीं की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि माननीय न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग ने रिकॉर्ड में कोई सामग्री न होने पर यह सुझाव देने के लिए कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रहे हैं, गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसलिए, 01.04.2013 का आदेश कानून में स्थायी नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा 30.05.2018 के आदेश द्वारा बिना विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए और बिना यह दर्ज किए कि याचिकाकर्ता फरार हैं या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे हैं, जो धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए आवश्यक है। रिकॉर्ड में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा कभी बनाई गई थी। संपत्ति की

जब्ती का आदेश पारित करते समय धारा 83 के तहत याचिकाकर्ताओं की संपत्ति को जब्त करने का विवरण दिए बिना पारित किया गया। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि 30.05.2018 का आदेश जिसके द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा बनाई गई थी और 11.07.2022 का आदेश जिसके द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत जब्ती आदेश पारित हुआ था, कानून के अनुसार नहीं होने के कारण रद्द और समाप्त किया जाए।

5. राज्य के लिए उपस्थित विशेष लोक अभियोजक ने जोरदार तरीके से 01.04.2013 का आदेश जो माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी , हजारीबाग द्वारा पारित हुआ था, 30.05.2018 का आदेश जो माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित हुआ था और 11.07.2022 का आदेश जो माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II रामगढ़ द्वारा पारित हुआ था, रद्द करने की प्रार्थना का विरोध किया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि यह तथ्य ही पर्याप्त है कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी , हजारीबाग ने जिस प्रकार से 01.04.2013 का आदेश पारित किया है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जिस प्रकार से 30.05.2018 का आदेश पारित किया है और माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II रामगढ़ ने जिस प्रकार से 11.07.2022 का आदेश पारित किया है, इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित न्यायिक अधिकारियों को यह संतुष्ट करने वाले रिकॉर्ड में सामग्री उपलब्ध थी कि गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने, उद्घोषणा आदेश और संपत्ति की जब्ती आदेश जारी करना उचित था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दी जाए।

6. बार में प्रस्तुत किए गए प्रतिकूल तर्कों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री को ध्यान से देखने के बाद, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 73 उन परिस्थितियों से संबंधित है जब वारंट किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह प्रावधान करता है कि माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर सकते हैं जो गैर-जमानती अपराध का आरोपी है और जो अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है।

7. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए; यह विवादित नहीं है कि संज्ञान लेने के बाद, याचिकाकर्ताओं को समन जारी किया गया था लेकिन समन कभी उन पर सेवा नहीं किया गया और समन की सेवा किए बिना गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसे कभी निष्पादित नहीं किया गया। फिर भी माननीय दंडाधिकारी, हजारीबाग ने 01.04.2013 के आदेश द्वारा गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जबकि रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं थी जो यह दर्शाती हो कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रहे थे। इस प्रकार, इस न्यायालय की विचारधारा में, 01.04.2013 का आदेश, जो माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित किया गया था, कानून में स्थायी नहीं है और इसे रद्द और समाप्त किया जाना चाहिए।

इसलिए, 01.04.2013 का आदेश, जो माननीय **प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी**, हजारीबाग द्वारा ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स केस संख्या 1/2011 में आरोपित अपराधों के लिए पारित किया गया था, धारा 27(बी) और धारा 27(डी) के तहत, रद्द और समाप्त किया जाता है।

8. जहां तक 30.05.2018 का आदेश है जो माननीय मुख्य न्यायिक **दंडाधिकारी**, हजारीबाग द्वारा पारित किया गया है, अब यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि वह न्यायालय जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करता है, उसे यह संतोष दर्ज करना चाहिए कि जिस आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा की जा रही है वह फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपा हुआ है। यदि न्यायालय उद्घोषणा जारी करने का निर्णय लेता है तो उसे याचिकाकर्ता की उपस्थिति का समय और स्थान अपने आदेश में उल्लेख करना चाहिए जिसमें धारा 82 के तहत उद्घोषणा की जाती है। जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है, चूंकि माननीय मुख्य न्यायिक **दंडाधिकारी**, हजारीबाग ने न तो यह संतोष दर्ज किया कि याचिकाकर्ता फरार हैं या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपे हुए हैं और न ही याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति का कोई समय या स्थान निर्धारित किया है। इस न्यायालय को इसमें कोई संकोच नहीं है कि माननीय मुख्य **न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना उक्त उद्घोषणा जारी करने का आदेश देकर अवैधता की है। इसलिए, 30.05.2018 का आदेश जो माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित किया गया था, कानून में स्थायी नहीं है और इसका निरंतरता कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह एक ऐसा मामला है जहाँ 30.05.2018 का आदेश जो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हजारीबाग द्वारा पारित हुआ था, रद्द और समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, 30.05.2018 का आदेश जो माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स केस संख्या 1/2011 में आरोपित अपराधों के लिए पारित हुआ था, धारा 27(बी) और धारा 27(डी) के तहत रद्द और समाप्त किया जाता है।**

9. जहां तक 11.07.2022 का आदेश है जो माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II रामगढ़ द्वारा पारित हुआ है, यह एक स्थापित सिद्धांत है कि वह न्यायालय जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत उद्घोषणा जारी करता है, वह किसी भी समय उद्घोषणा जारी करने के बाद लिखित रूप में रिकॉर्ड में कारण दर्ज कर सकता है ताकि किसी भी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया जा सके जो घोषित व्यक्ति की हो। अब, यदि रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं है जो यह सुझाव देती हो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा वास्तव में कानून के अनुसार बनाई गई थी, तो निश्चित रूप से माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II रामगढ़ ने संपत्ति की जब्ती का आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ताओं की संपत्ति का विवरण बताए बिना अवैधता की थी और बिना किसी कारण को लिखित रूप में दर्ज किए बिना ऐसा आदेश पारित किया।

10. इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को कोई संशय नहीं है कि 11.07.2022 का आदेश जो माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II रामगढ़ द्वारा ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स मामला संख्या 1/2011 के संबंध में पारित किया गया था, वह भी कानून के अनुसार नहीं है और यह एक गंभीर अवैधता है। इसका निरंतरता कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक ऐसा मामला है जहाँ 11.07.2022 का आदेश जो माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II रामगढ़ द्वारा ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स मामला संख्या 1/2011 के संबंध में पारित किया गया था, रद्द और समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार, 11.07.2022 का आदेश जो माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II रामगढ़ द्वारा ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स मामला संख्या 1/2011 में पारित किया गया था, रद्द और समाप्त किया जाता है।

11. याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II रामगढ़-सम विशेष न्यायाधीश, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम मामलों के समक्ष इस आदेश की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आश्वासन देते हैं।

12. यदि याचिकाकर्ता इस आदेश की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II रामगढ़-सम विशेष न्यायाधीश, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम मामलों के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश II रामगढ़ कानून के अनुसार नया आदेश पारित कर सकते हैं।

13. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकार की जाती है।

(**न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी**)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 7 दिसंबर, 2023

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|